RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

E-mail : coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 31 जुलाई, 2015 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 12, अंक : 2

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

आप सबको ईद की हार्दिक बधाई ! हमें आशा है कि ईद का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया गया होगा।

आलू के सम्बन्ध में जितने भी समाचार आ रहे हैं वह उत्साहवर्धक नहीं हैं। देश की विभिन्न मण्डियों में 300 से 600 रुपये कुन्तल के रेट तक का आलू बिक रहा है जिसमें भण्डारणकर्ता को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। इसी कारण निकासी बहुत धीरे चल रही है। अभी तक मात्र 30% तक की निकासी के समाचार मिले हैं।

हाथरस से शिवांग कोल्ड स्टोरेज के मालिक श्री मोहित अग्रवाल ने हमें सूचित किया है कि इस समय आलू के रेट 400 रूपए से 550 रूपए कुन्तल चल रहे हैं। CIPC आलू के रेट 400 रूपए से 650 रूपए कुन्तल चल रहे हैं। आपको आशा है की भविष्य में आसाम की माँग अच्छी हो सकती है और वहाँ उत्तर प्रदेश से भी आलू जा सकता है। हमारे संज्ञान में आया है कि शीतगृहों में आलू 300 से 550 रूपए कुन्तल बिक रहा है वही पर फुटकर आलू 15 रुपये किलो से कम नहीं बिक रहा है।

इसके माने यह हुए कि थोक से फुटकर में ब्रिकी में जो अन्तर बनता है वो चाहे ज्यादा मुनाफे के कारण बनता हो या अधिक खर्चे आ जाने के कारण बनता हो परन्तु यह अन्तर बहुत ज्यादा है और आलू की बिक्री पर बहुत बुरा असर डाल रहा है।

हमारी सलाह है कि इस विषय पर जनपद स्तरीय कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन को अवश्य विचार करके कदम उठाना चाहिए। वह अपने साथ शीतगृहों को जोड़े और जगह–जगह कम रेट पर आलू बिकवाने की व्यवस्था करें। इसमें हो सकता है आलू बिक्री में कोई मुनाफा न हो, लेकिन घाटा भी नहीं होगा और इतना फायदा जरूर हो जायेगा कि आलू की निकासी बहुत तेज हो जाएगी।

शीतगृहस्वामी इतना अवश्य ध्यान कर लें कि उन्हें आलू की निकासी में अथक प्रत्यन करने पड़ेंगे तभी कही जाकर इस वर्ष आलू की निकासी सही रूप से हो पायेगी। काफी जगह से आलू दागी और खराब होने के समाचार आ रहे है। यदि शीतगृहस्वामी स्वयं हमारे द्वारा बताए गए तरीके से आलू ब्रिकी शुरू कर देंगे, वह आलू भी शीतगृहों से आसानी से निकल जायेगा जिस आलू के इस वक्त खरीदार नहीं मिल रहे हैं क्योंकि शीतगृहों में जो आलू बिकता है वह बाहर लोडिंग के लिए माँगा जाता है। हल्की क्वालिटी का आलू लोकल मण्डी में तो चल जाता है, बाहर की मण्डियों में नहीं चल पाता, इसलिए शीतगृहस्वामियों को तुरन्त मिलकर यह कदम उठाना चाहिए। मिल के चलने में खर्च भी कम आयेगा और यदि इसका प्रचार–प्रसार किया जाए कि यह कदम शीतगृहों द्वारा उपभोक्ताओं के हित में उठाया गया है तो शीतगृहों की समाज व सरकार में छवि भी सुधरेगी।

यह आलू छोटी–छोटी ट्रकों में पाँच–पाँच किलो के पैकेटों में सुविधापूर्वक बेचा जा सकता है। इससे छोटे तौल में बेचने में परेशानी आ सकती है। छोटी ट्रकों को कही पर भी खड़ा करके आलू की ब्रिकी शुरू की जा सकती है। ट्रक पर बैनर लगाना आवश्यक होगा। हमें पूरी आशा है ग्राहक 10 रूपए किलो तक भी इसका भरपूर स्वागत करेंगे।

बिजली सम्बन्धी–रेगुलेटरी सर्चार्ज के सम्बन्ध में :

हमारे मई, 2015, पत्रिका अंक में हमने अपने सदस्यों को सूचित किया था कि LMV6 और HV2 श्रेणी के उपभोक्ताओं से Regulatory Surcharge 1 और 2, 1 अप्रैल, 2015 से हटा लिए गए है। अभी हमें Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission का नया स्पष्टीकरण मिला है, जिसे हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

इस आदेश के अनुसार रेगुलेटरी सरचार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है और वह रेगुलेटरी सरचार्ज वैसा का वैसा ही चार्ज किया जायेगा।

Sanjay Srivastava
Secretary

Ref. : UPERC/Secy/D(Tariff)/15-561
Dated : June 17, 2015

To,

1. Chairman, U.P. Power Corporation Ltd., Shakti Bhawan, 14, Ashok Marg,Lucknow-226001.
2. MD, U.P. Power Corporation Ltd., Shakti Bhawan, 14, Ashok Marg, Lucknow - 226001.
3. MD, MVVNL, 4-A, Gokhale Marg, Lucknow - 226001.
4. MD, DVVNL, Urja Bhawan, 220KV Sub-Station, Mathura Bypass Road, Agra - 282007.
5. MD, PVVNL, Victoria Park, Meerut - 250001.
6. MD, PuVVNL, Bhikharipur, 132KV Sub-Station, Poorvanchal Vidyut Bhawan, P.O. Diesel Locomotive Works, Varanasi - 221004.
7. MD, KESCo, KESA House, 14/71, Civil Lines, Kanpur - 208001.
8. CE, RAU, Regulatory Affairs Unit, U.P. Power Corporation Ltd., 15thFloor, Shakti Bhawan Extension, 14, Ashok Marg, Lucknow – 226001.

Subject : Applicability of Regulatory Surcharges for State Distribution Licensees for FY 2015-16 as per Commissions Orders dated June 6, 2014 and October 1, 2014

Sir,

The Commission has received a letter from UPPCL dated June 9, 2015 seeking clarification on the applicability of Regulatory Surcharge-1 on the various categories of consumers as approved in the Commission's Suo-Moto Order dated April 22, 2015 in the above matter.

The last para of the said order is reproduced as follows :

"It is to be noted that as the efforts for reduction in line losses have been mostly directed at the domestic and agriculture consumers, the revised Regulatory Surcharge-1 & Regulatory Surcharge-2 for FY 2015-16 as approved in this order, would only be applicable for the consumer of LMV-1 & LMV-5 categories only."

From the above, it can be seen that there is clear intention of reducing the Regulatory Surcharges only for the consumers of LMV-1 & LMV-5 categories. However to give more clarity on the applicability issue, the Commission clarifies that for the rest of the consumers categories (except LMV-1 & LMV-5 categories), the Regulatory Surcharge-1 & Regulatory Surcharge-2 for FY 2015-16 will continue to be same as was applicable for FY 2014-15.

The licensees are directed to issue public notices in newspapers in regard to the above clarification so as the same is widely publicised.

This clarification is issued with the approval of the Commission.

Yours sincerely,

Sanjay Srivastava

Secretary

बिसौली के शीतगृहों का प्रशंसनीय कार्य :

श्री सुभाष अग्रवाल, अध्यक्ष, बदायूँ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, बिसौली ने तहसील बिसौली, जिला बदायूँ के 16 शीतगृहों के सहयोग से 65,000 रूपए का दान नेपाल भूकम्प त्रासदी के लिए दिया। यह एक सराहनीय कार्य है। इसकी सराहना श्री गुलाब चन्द पी.सी.एस, उप–जिला अधिकारी, बिसौली ने की।

विद्युत सम्बन्धी :

हम अपने सदस्यों को Security पर मिलने वाले ब्याज के बारे में बराबर सूचित करते आ रहे हैं। अभी हमें दो नए Circular मिले हैं जो कि वित्त वर्ष 2014–15 के लिए व वित्त वर्ष 2015–16 के लिए है। यह Circular दिखाकर आप अपने Security पर मिलने वाले ब्याज को ठीक करवा सकते है।

BEFORE THE UTTAR PRADESH
ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, LUCKNOW

In the matter of :

Specifying the rate of interest on security deposited by a person for electricity supply for the year 2014-15.

In the matter of :

1. Managing Director, UP Power Corporation Ltd., 7th Floor, Shakti Bhawan, 14, Ashok Marg, Lucknow.
2. Managing Director, Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., 4-Gokhale Marg, Lucknow.
3. Managing Director, Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., Victoria Park, Meerut.
4. Managing Director, Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., Urja Bhawan 220, K.V. UP-Sansthan Bypass Road, Agra-282007
5. Managing Director, Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., Purvanchal Vidyut Bhawan, P.O. Vidyut Nigam, DLW, Varanasi.
6. Managing Director, Kanpur Electricity Supply Co. Ltd., 14/71, Civil Lines, KESA House, Kanpur.
7. Managing Director & CEO, Noida Power Company Ltd., Commercial Complex H-Block, Alpha Sector II, Greater Noida-201308

Order No. 6

In reference to section 47 (4), of the Electricity Act 2003, the distribution licensee shall pay interest, on the security deposited by a person for supply of electricity. The Commission specifies rate of interest on such Security at the bank rate of 9% as specified by Reserve Bank of India for 1st April 2014, this rate of interest shall be applicable for the financial year 2014-2015. This rate of interest shall be payable to consumers as per clause 4.20 (i) of the Electricity Supply Code, 2005.

Managing Directors of all distribution licensees are directed to issue necessary instructions to their field/billing staff and take necessary action for information of the general public.

With the approval of the Commission

(Sanjay Srivastava)

Secretary

Date : 28.5.2015

BEFORE THE UTTAR PRADESH

ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, LUCKNOW

In the matter of :

Specifying the rate of interest on security deposited by a person for electricity supply for the year 2015-16.

In the matter of :

1. Managing Director, UP Power Corporation Ltd., 7th Floor, Shakti Bhawan, 14, Ashok Marg, Lucknow.
2. Managing Director, Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., 4-Gokhale Marg, Lucknow.
3. Managing Director, Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., Victoria Park, Meerut.
4. Managing Director, Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., Urja Bhawan 220, K.V. UP-Sansthan Bypass Road, Agra-282007
5. Managing Director, Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., Purvanchal Vidyut Bhawan, P.O. Vidyut Nigam, DLW, Varanasi.
6. Managing Director, Kanpur Electricity Supply Co. Ltd., 14/71, Civil Lines, KESA House, Kanpur.
7. Managing Director & CEO, Noida Power Company Ltd., Commercial Complex H-Block, Alpha Sector II, Greater Noida-201308

Order No. 7

In reference to section 47 (4), of the Electricity Act 2003, the distribution licensee shall pay interest, on the security deposited by a person for supply of electricity. The Commission specifies rate of interest on such Security at the bank rate of 8.5% as specified by Reserve Bank of India for 1st April 2015, this rate of interest shall be applicable for the financial year 2015-2016. This rate of interest shall be payable to consumers as per clause 4.20 (i) of the Electricity Supply Code, 2005.

Managing Directors of all distribution licensees are directed to issue necessary instructions to their field/billing staff and take necessary action for information of the general public.

With the approval of the Commission

Date : 28.5.2015

(Sanjay Srivastava)

Secretary

वर्ष 2015–16 के नए टैरिफ के सम्बन्ध में :

हमने अपने पिछले अंक के वर्ष 2015–16 का HV2 का नया टैरिफ दिया था।

हम यहाँ पर आपको उस टैरिफ में किए गए कुछ बदलाव के बारे में बतलाना चाहते है कि जिससे आपको उसे समझने में आसानी हो जाए।

टैरिफ के General Provisions के बिन्दु 7 पर ध्यान दें। इस पर लेट पेमेन्ट पर सरचार्ज 1.5 प्रतिमाह से घटाकर 1.25% प्रतिमाह कर दिया गया है जो कि पहले तीन महीने तक लागू रहेगा, उसके बाद बिल मे देर से पेमन्ट होने पर 2% प्रतिमाह कर दिया गया है। इसी बिन्दु 7 जिसमें सरचार्ज व पेमन्ट दी हुई है कि बिन्दु 2 (ii) (b) पर ध्यान दे यह पूरा नियम नया बनाया गया है। इसमे डिमाण्ड चार्ज से माँग बढ़ जाने पर उपभोक्ता को किस प्रकार अपने को संतुलित करना चाहिए यह नियम दिया है जिसे आप ध्यान से अवश्य पढ़ें।

बिन्दु नम्बर : 9 जिसमें रुके हुए पेमेन्ट पर कुछ छूट प्रदान की गई भी अब पूरी तरह हटा दी गई है। इसे भी पूरा ध्यान से पढ़िए।

बिन्दु नम्बर : 13 इसमें मई 11, 2015 पर Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission,

का नया आदेश आया है जो कि Prepaid मीटर पर आया है। यदि आपके यहाँ Prepaid मीटर लग गया हो तो इसे अवश्य पढ़ लें। वैसे अभी 45 के.वी.ए. से ऊपर के Connection पर Prepaid Meter नही लगने शुरू हुए हैं।

नये टैरिफ में बिन्दु नम्बर : 19, 20, 21, 22 बिलकुल नये लगाए गये है।

इस नये टैरिफ में पावर रेट में डिमांड चार्ज में कोई तबदीली नहीं की गई है केवल बिजली के यूनिट चार्ज जो पहले 6.30 के.वी.ए. थे अब 6.65 प्रति के.वी.ए. कर दिए गए है।

केवल ऐसे उपभोक्ताओं को विशेष छूट दी गई है जो अपना सारा लोड रात के 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे के बीच में रखते है और बाकी के समय में उनका लोड अपने Contracted load से 15% से ज्यादा नहीं बढ़ता, ऐसे उपभोक्ताओं को 15% की छूट दी जायेगी। इसे आप Rate Schedule HV2 के बिन्दु 3 में विस्तार से पढ़ सकते हैं। सीजनल Industry की अन्य छूट में कोई बदलाव नहीं है।

RATE SCHEDULE LMV – 1

DOMESTIC LIGHT, FAN & POWER

1. APPLICABILITY :

This schedule shall apply to :

(a) Premises for residential / domestic purpose, Paying Guests / Domestic purpose (Excluding Guest Houses), Janata Service Connections, Kutir Jyoti Connections, Jhuggi / Hutments, Places of Worship (e.g. Temples, Mosques, Gurudwaras, Churches) and Electric Crematoria.

(b) Mixed Loads

(i) 50 kW and above

(a) Registered Societies, Residential Colonies / Townships, Residential Multi-Storied Buildings with mixed loads (getting supply at single point) with the condition that 70% of the total contracted load shall be exclusively for the purposes of domestic light, fan and power. The above mixed

load, within 70%, shall also include the load required for lifts, water pumps and common lighting,

(b) Military Engineer Service (MES) for Defence Establishments (Mixed load without any load restriction).

(ii) Less than 50 kW

Except for the case as specified in Regulation 3.3 (e) of Electricity Supply Code, 2005 as amended from time to time, if any portion of the load is utilized for conduct of business for non-domestic purposes then the entire energy consumed shall be charged under the rate schedule of higher charge

2. CHARACTER AND POINT OF SUPPLY :

As per the applicable provisions of Electricity Supply Code.

3. RATE :

Rate, gives the fixed and energy charges at which the consumer shall be billed for his consumption during the billing period applicable to the category :

(a) Consumers getting supply as per 'Rural Schedule' :

Description	Description	Fixed charge	Energy charge
(i) Un-metered*	Load up to 2 kW	Rs. 180/kW/month	Nil
	Load above 2 kW	Rs. 200/kW/month	Nil
(ii) Metered	All Load	Rs. 50/kW/month	Rs. 2.20/kWh

***Note :** All the unmetered consumers of LMV-1(a) i.e. Consumers getting supply as per "Rural Schedule" shall be converted into metered connection by December 31, 2015 beyond which the Tariff for unmetered category of LMV-1(a) shall be increased by 10%.

(b) Supply at Single Point for bulk loads (50 kW and above, Supplied at any Voltage) :

Description	Fixed Charge	Energy Charge
For Townships, Registered Societies, Residential Colonies, multi-storied residential complexes (including lifts, water pumps and common lighting within the premises) with loads 50 kW and above with the restriction that at least 70% of the total contracted load is meant exclusively for the domestic light, fan and power purposes and for Military Engineer Service (MES) for Defence Establishments (Mixed load without any load restriction).	Rs. 85.00 / kW / Month	Rs. 5.50 / kW

The body seeking the supply at Single point for bulk loads under this category shall be considered as a deemed franchisee of the Licensee. Such body shall charge not more than 10% additional charge on the above specified Rate from its end consumers apart from other applicable charges such as Regulatory Surcharge, Penalty, Rebate and Electricity Duty on actual basis.

The franchisee is required to provide to all its consumers and the licensee, a copy of the detailed computation of the details of the amounts realized from all the individual consumers and the amount paid to the licensee for a certain billing cycle. If he fails to do so, then the consumers may approach the Consumer Grievance Redressal Forum having jurisdiction over their local area for the redressal of their grievances.

(c) Other Metered Domestic Consumers :

1. Lifeline consumers : Consumers with contracted load of 1 kW, energy consumption up to 150 kWh / month.

Description	Fixed Charge	Energy Charge
Loads of 1 kW only and for consumption up to 50 kWh/month (0 to 50 kWh/month)	Rs. 50.00 / kW / month	Rs. 2.00 / kWh
Loads of 1 kW only and for consumption above 50 kWh / month up to 150 kWh / month (51 to 150 kWh / month)		Rs. 3.90 / kWh

2. Others : Other than life line consumers (i.e. consumers who do not qualify under the criteria laid down for lifeline consumers.)

Description	Consumption Range	Fixed Charge	Energy Charge
All loads	Upto 150 kWh / month	Rs. 90.00 / kW / month	Rs. 4.40 / kWh
	151 - 300 kWh / month		Rs. 4.95 / kWh
	301 – 500 kWh / month		Rs. 5.60 / kWh
	Above 500 kWh / month (From 501st unit onwards)		Rs. 6.20 / kWh

Note :

1. For all consumers under this category the maximum demand during the month recorded by the meter has to be essentially indicated in their monthly bills. However, this condition would be mandatory only in case meter reading is done by the Licensee. Accordingly, if the bill is being prepared on the basis of reading being submitted by the consumer then the consumer would not be liable to furnish maximum demand during the month and his bill would not be held back for lack of data on maximum demand.

बैंकॉक में हुई मीटिंग के सम्बन्ध में :

दिनांक जुलाई, 22, 23, 24, 2015 को बैंकॉक में Federation of Cold Storage Associations of India की मीटिंग वा मशीनरी निर्माताओं के विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस मीटिंग में करीब 150 फेडरेशन के सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

इस मीटिंग की विशेषता यह भी थी कि इसमें Asia के अन्य देशों की Associations के प्रतिनिधि भी आमंत्रित थे, जिसमें विभिन्न प्रकार के शीतगृह वह कोल्ड चेन के प्रतिनिधि थे। जिन देशों के साथ हमारी मीटिंग हुई वह इस प्रकार थे :–

(1) Thailand (2) China (3) Bhutan

(4) Phillipines (5) Myanmar (6) Indonesia

उपरोक्त देशों से आए प्रतिनिधियों ने अपने देश में शीतगृहों व कोल्ड चेन की स्थिति के बारे में सूचनाएं दीं। प्रायः सभी जगह पर शीतगृहों में मीट, मछली वा अन्य तैयार खाद्य पदार्थों का ही भण्डारण होता है। सब्जी का भण्डारण प्रायः नहीं किया जाता क्योंकि इसमें शीतगृहों को लाभ नहीं

पहुँचता। सब्जियों को लाने ले जाने के लिए कोल्ड चेन वाले अवश्य सक्रिय रहते हैं। और अधिक जानकारी यदि हमें मिली तो हम अगले अंक में प्रकाशित करेंगे।

यहाँ पर हम बैंकॉक की मीटिंग के कुछ चित्र दे रहे हैं।

(12) – पत्रिका कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, जुलाई, 2015

2. Food Safety and Standards Act, 2006 के बारे में :

हमने दिनांक 28.7.2015 को माननीय स्वास्थ मंत्री, से मिलकर उन्हें अपना प्रतिवेदन देना था और हमारे पिछले पत्रों के बारे में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी भी लेनी थी लेकिन भूतपूर्व राष्ट्रपति के स्वर्गवास के कारण वह मीटिंग नहीं हो पाई। अब एक दो दिन में Shri Rakesh Garg, Co-ordinator International Affairs, Federation of Cold Storage Associations of India, माननीय स्वास्थ मंत्री वा स्वास्थ सचिव से मिलेंगे और हालात की पूरी जानकारी देंगे जिसे हम अगले अंक में प्रस्तुत करेंगे। हमारी अभी तक की जानकारी के अनुसार शीतगृहों को Food Safety and Standards Act, 2006 में शमिल करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

हमने जो पत्र माननीय स्वास्थ मंत्री को देना है उसे हम यहाँ आपके संज्ञान में भी लाना चाहते हैं, जिससे हमारे सदस्यों को ज्ञात रहे कि हम अपने पक्ष से Food Safety and Standards Act, 2006 के विरोध में क्या तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं।

Federation : 2015/91 July 27, 2015

Hon. Minister of Health & Family Welfare,
Government of India,
Nirman Bhawan, New Delhi

Sir,

Subject : Request for Exemption of Cold Storages from Food Safety and Standards Act 2006.

Reference : Our letter of request dated 27th April, 2015.

We request you to exempt cold storages from Food Safety And Standards Act 2006, and wish to bring the following facts to your kind notice :-

Some States of India have got their State Acts which come in the way of the Food Safety And Standards Act 2006. Following are the clauses of The Uttar Pradesh Regulation of Cold Storages Act 1976.

Section 14 (1) of the Uttar Pradesh Regulation of Cold Storages Act 1976 comes in way of Food Safety and Standards Act 2006.

Section 14 (1) is as follows :-

Provided that a licensee shall not refuse to store potato seed of bona fide cultivators, so certified in the prescribed form and manner by a Gazetted officer of Horticulture Department or a Block Development Officer, as the case may be, on the ground that it is likely to cause damage to other agricultural produce.

In this case if the bona fide potato cultivator brings his seed in deteriorating condition and insists on its preservation inside the cold storage, then the cold storage owner can not refuse to store on the ground that it is likely to cause damage to other agricultural produce. This causes a clear violation of the Food Safety and Standards Act, 2006.

Similarly, Section 17(1) & (2) The Uttar Pradesh Regulation of Cold Storages Act 1976 comes in way of Food Safety and Standards Act, 2006.

Section 17 (1) & (2) read as follows:

Section 17(1) Whenever goods stored in a cold storage begin to deteriorate or are likely to deteriorate from the cause beyond the control of the licensee, or where the hirer fails to take delivery of the goods in the cold storage with a period of fifteen days from the date specified thereof in the receipt, the licensee shall forthwith give notice thereof to the hirer, requiring him to take delivery of the goods immediately after surrendering the receipt duly discharged and paying all charges due to the licensee, and send a copy of such notice to the licensing officer.

Section 17 (2) Where the hirer fails to comply with the notice referred to in subsection (1) within a period of seven days from the date of service thereof, the licensee may cause the goods to be removed from the cold storage and sold by the public auction at the cost and risk of their hirer.

Provided that the Licensee shall give notice of the sale to the Licensing Officer at least forty-eight hours before such sale, and the Licensing Officer shall supervise such sale either himself or through an officer authorized by him in that behalf.

Please note that the already deteriorating stock can not wait for long and further should not be kept in the Cold Storage under Food Safety and Standards Act, 2006.

Here if the cold storage owner finds any defect in the potato inside the cold storage, then as per the compliance of the Food Safety and Standards Act, 2006 he is supposed to take out that stock and ensure that stock is not sold to any one for human consumption but under this section of The Uttar Pradesh Regulation of Cold Storages Act 1976.when he finds that stock of potato begins to deteriorate or likely to deteriorate from the cause beyond the control of the licensee, cold storage owner has to give notice to the hirer requiring him to take delivery of the goods which is clear violation of the Food Safety and Standards Act, 2006. Further cold storage owner has to wait for another period of seven days from the date of service of the first notice and sell the goods by public auction. If such goods are auctioned then there is a good likelihood of their going to the vegetable market or any other

market, for human consumption against the spirit of Food Safety and Standards Act, 2006

Further, we want to state that particularly in case of potato cold storages where the capacities are large, ranging from 1 lakh to 4 lakh packets and the entire loading of the cold storages are to be done within a period of 15-20 days it is practically not possible for a cold storage owner to inspect the goods, as, on an average 10-15 thousand packets are received per day which are to be loaded in the cold storage chamber.

It is also not practically possible to inspect, if at all, the damaged potato, already loaded inside the cold storage chamber, thoroughly.

With the various difficulties and the legal lacunas as pointed out in our letter, we humbly request you to exempt this upcoming small scale industry from the Food Safety and Standards Act, 2006.

Thanking you,

For **FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA**
(MAHENDRA SWARUP)
PRESIDENT

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2014-16

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित